

संपादकीय

पीएम संबोधन में शिक्षा गायब

पांच सितंबर को ‘शिक्षक दिवस’ आया और चला गया। कुछ रस्मी आयोजन जरूर किए गए। देश में यह दिवस प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वह महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। राधाकृष्णन की अदम्य और विनम्र इच्छा थी कि उनका जन्मदिन शिक्षा और शिक्षकों को समर्पित किया जाएगा, तो अच्छा रहेगा। 1962 से यह सिलसिला जारी है कि 5 सितंबर को ‘शिक्षक दिवस’ मनाया जाता है। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक को ‘नियति का निर्माता’ करार दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से मुलाकात की। उनके साथ हल्के-फुल्के पल भी जिए। बच्चों के संदर्भ में स्क्रीन टाइम और नशे की लत से बचाने की नसीहत भी दी। इसी दिन प्रख्यात श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ‘शताब्दी समारोह’ भी मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे और उन्होंने छात्रों को युवा पीढ़ी, जेन-जी, को संबोधित भी किया। अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री शिक्षा, स्कूल, परीक्षा और रोजगार पर सरकार की नीतियों और विचारार्थीन कार्यक्रमों, योजनाओं पर कुछ साझा करेंगे, लेकिन उनका संबोधन 2013 की स्थितियों और ‘आधा गिलास खाली’ की राजनीति पर ही केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि 2014 से पहले का कालखंड निराशा, हताशा के दलदल में फंसा था। घोटाले चरम पर थे।

विकास फर्श पर और महंगाई अंश पर थी। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप इंटरनेट खोल कर सब कुछ पढ़ें और जान सकेते हैं कि तब हालात क्या थे? दरअसल हमारा सवाल यहीं उभरता है कि क्या अध्ययनरत छात्रों का यही सरोकार होना चाहिए? उन्हें शिक्षा, परीक्षा, रोजगार के प्रति आश्वास्य नहीं किया जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री का संबोधन था, न कि एक विशुद्ध राजनेता छात्रों के साथ संवाद कर रहा था! यहां हम कुछ आंकड़े फिर दोहरा रहे हैं, ताकि पाठक और सरकार जान सकें कि देश में स्कूली शिक्षा और आधारभूत ढांचे का यथार्थ क्या है? 2014–25 के दौरान 1.02 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और 1.04 लाख स्कूलों में एक ही अध्यापक (शिक्षक ?) है। क्या वह अपने शिक्षक-धर्म को निभा सकता है? करीब 70,000 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है, 55083 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, 4.08 लाख स्कूलों में कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है, 46345 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और देश के 48 फीसदी छात्र सरकारी स्कूलों से ही शिक्षित होने को बाध्य हैं। करीब 48 फीसदी छात्र 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। ऐसे यथार्थ में हम एक पर्याप्त पढ़ी-लिखी, हुनरमंद जेन-जी की पीढ़ी कैसे पैदा कर सकते हैं? ऐसे कई आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान में होंगे! उन्हें ‘शिक्षक दिवस’ पर कौन-सा प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा? छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की खूब गालबजाई की। पहली तिमाही की विकास दर 7.8 फीसदी को ‘अतुलनीय’ और वैश्विक करार दिया।

साझी संस्कृति की अनूठी ऐतिहासिक नंदा राजजात यात्रा

नंदा देवी राजजात उत्तराखंड की अनूठी धार्मिक-आध्यात्मिक रात्रा है, जो मां नंदा को ध्यान के रूप में कैलास विदा करने की भावुक परंपरा, लोकविश्वास, इतिहास और रोमांच को समेटे हुए है।

नंदा राजजात का धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्त्व है। यह यात्रा रहस्य और रोमांच से भरपूर है। 9वीं सदी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने यह यात्रा शुरू की। तब से यह धार्मिक यात्रा हर 12 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। हालांकि, सन 1905 से 2014 के बीच अब तक केवल सात बार यह यात्रा आयोजित की गई। यात्रा में 280 किलोमीटर तक बर्फीले रास्तों और कठिन रास्तों से होकर अंतिम पड़ाव रूप कुंड (होमकुंड) में पहुंचा जाता है। खास बात यह कि यात्रा की अगुवाई चार सींगों वाला भेड़ (चौसिंग्या खाडू) करता है। इस यात्रा को एशिया की सबसे लंबी और कठिन पैदल धार्मिक यात्रा माना जाता है,उत्तराखंड देवभूमि में मां नंदा केवल देवी नहीं, बल्कि पहाड़ की विवाहित बेटी (ध्यान) के रूप में मान्यता रखती हैं।

नंदा राजजात महज यात्रा नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है। यह अपनी ध्याणी (विवाहिता बेटी) को मायके से समुराल (कैलाश पर्वत) विदा करने का अनूठा और भावुक लोक-उत्सव है। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में नंदा-जात (छोटी जात) आयोजित होती हैं। लेकिन नंदादेवी राजजात तय समय में परंपरा और शास्त्रों के अनुसार ही आयोजित की जाती है।

280 किमी का कठिन-निर्जन सफ़र

उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद चमोली के नौटी गांव से शुरू होकर यात्रा उच्च हिमालय क्षेत्र होमकुंड पर ठहरती है। समुद्र की गहराई से 17,500 फीट की ऊंचाई तक जाने वाली यह यात्रा 20 दिनों में पूरी होती है। पैदल और कड़ाके की ठंड। श्रद्धालु कड़ाके की ठंड, घने जंगलों, खड़ी चट्टानी चढ़ाईयों और ऑक्सीजन की कमी वाले रास्तों से गुजरते हैं।

रिंगाल से बनती पवित्र छंतोली

राजजात की अगुवाई के लिए रिंगाल (विशेष प्रजाति का पहाड़ी बांस) से बनी एक छतरी बनाई जाती है। इसे छंतोली कहा जाता है। स्थानीय मान्यतानुसार इसको मां नंदा का प्रतीक मानकर पूरे रास्ते अत्यंत श्रद्धा से ले जाया जाता है। इसको लेकर जाने वालों को पूरे नियम और संयम का पालन करना होता है।

यात्रा से पहले दो धार्मिक आयोजन

नंदादेवी राजजात आयोजन से पहले दो प्रमुख धार्मिक आयोजन होते हैं। इसमें एक मोडवी और दूसरा मनौती। मोडवी उत्सव में स्थानीय क्षेत्रपाल और उफराई देवी की पूजा-अर्चना की जाती है।

मोडवी के बाद चौसिंग्या मेड़ा के उत्पन्न होने की सूचना राजकुंवरो को विधिवत रूप से दी जाती है। इसके बाद राजकुंवर मां नंदा से मनौती मांगते हैं। इसके बाद राजकुमारों द्वारा मां नंदा से मनौती मांगी जाती है।

चौसिंग्या खाडू (चार सींगों वाली भेड़)

इस यात्रा में चार सींगों वाला नर भेड़ (चौसिंग्या खाडू) केंद्र में होता है। लोक-मान्यता है कि जब 12 साल बाद राजजात का समय आता है, तो चांदपुर गढ़ी क्षेत्र के किसी भी गांव में चार सींगों वाला भेड़ जन्मता है। जो चौसिंग्या खाडू मान्यता और शास्त्रों के अनुरूप खरा उतरता है, उसका चयन किया जाता है। चौसिंग्या खाडू के चयन का अधिकार कासवा गांव, चांदपुर क्षेत्र और राजवंशी कुंवरो के पास है। इसके बाद राजकुंवरों द्वारा मां से मनौती मांगी जाती है। चौसिंग्या खाडू बिना किसी रस्सी या किसी सहायता के यात्रा की अगुवाई करते हुए 280 किलोमीटर तक स्वयं रास्ता दिखाता है।

अकेले कैलास की ओर प्रस्थान

होमकुंड में अंतिम पूजा और अन्य अनुष्ठान के बाद यह चौसिंग्या खाडू मां नंदा देवी के वस्त्र, आभूषण और प्रसाद अपनी पीठ पर लादकर

सीधा संवाद

जीडीपी से नहीं, जमीन पर नजर आए बदलाव

भारत में सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 65 फीसदी हिस्सा है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 फीसदी लोग राष्ट्रीय आय का 58 फीसदी हिस्सा पाते हैं, जबकि सबसे निचले 50 फीसदी लोगों को सिर्फ 15 फीसदी मिलता है। आर्थिक असमानता की यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का यह हक है कि जीडीपी की ग़ोथ पर खुशी मनाने का आह्वान करें, पर जब तक इसका असर देश की मूल समस्याओं के निराकरण में नजर नहीं आएगा, देश के लोगों की उदासी दूर नहीं होगी। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार देना होगा। बड़ी संख्या में युवा अभी बेरोजगार हैं। उन्हें उनकी शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, फिर भी अभी और काम करने की जरूरत है। रोजगार मिलने से कई समस्याएं हल हो जाएंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की तरक्की का जश्न मनाने के लिए कहते हुए 7.8 फीसदी की शानदार जीडीपी ग्रोथ के लिए बधाई दी। सवाल यह है कि क्या आम आदमी देश में जीडीपी ग्रोथ को समझता है। क्या जीडीपी बढ़ना देश की मौजूदा समस्याओं के समाधान का कोई पैमाना है। देश में जब प्रधानमंत्री जीडीपी बढ़ोतरी की घोषणा कर रहे थे, उसी दिन कमर्शियल एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में इसके दाम में 9.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2747.50 रुपए, मुंबई में 2701 रुपए और चेन्नई में 2916.50 रुपए हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से होटल, ढाबे आदि में खाना-पीना महंगा होना तय है। वहीं घर मिलने वाली चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 5 किलो वाले गैस सिलेंडर का भी दाम 2 रुपए बढ़कर 764 रुपए हो गया है।

मुंबई और तमिलनाडु में दूध महंगा हो गया है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमतों में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे दूध की थोक दर 93 रुपए से बढ़कर 102 रुपए प्रति लीटर हो गई है। भारत में जुलाई-अगस्त 2026 के दौरान खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.52 प्रतिशत हो गई है, जिसके कारण चीनी, प्याज, टमाटर, दाल और खाना पकाने के तेल जैसी जरूरी रसोई की चीजें महंगी हो गई हैं। चावल और दूध के दाम भी स्थिर से लेकर उच्च स्तर पर बने हुए हैं। महंगाई बढ़ने के कारण प्याज (22.54 फीसदी), लहसुन (35.36 फीसदी) और अदरक (83.62 फीसदी) की कीमतों में भारी तेजी आई है। ईंधन और परिवहन महंगाई बढ़कर 4.43 फीसदी हो गई है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है। रेस्त्रां और आवास सेवाओं की महंगाई दर बढ़कर लगभग 7.72 फीसदी हो गई है। देश के आम आदमी को हर दिन होने वाली कठिनाइयों से जुझना पड़ रहा है। देश का मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को जीडीपी की ग्रोथ से अंतर तब पड़ता है, जब उनकी बुनियादी सुविधाओं में कोई बेहतरि नजर आए।

देश में पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार, महंगाई जैसी बुनियादी समस्याओं की भरमार है। इनसे राहत मिलती भी है तो ऊंट के मुंह में जीरे जितनी। इससे बदलाव नजर नहीं आता। भारत की आधी से अधिक आबादी यानी करीब 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। देश के भूजल का बड़ा हिस्सा आर्सेनिक, फ्लोराइड



और अन्य भारी धातुओं (हैवी मेटल्स) की वजह से दूषित हो चुका है। बारिश का पर्याप्त पानी होने के बावजूद उचित हार्वेस्टिंग (संचयन) न होने के कारण पानी बेकार बह जाता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, साफ पीने का पानी न मिलने के कारण हर साल देश में करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वर्ष 2026 में भीषण गर्मी, रिकॉर्ड बिजली मांग (मई 2026 में 270 गीगावाट से अधिक) और स्थानीय रखरखाव के कारण उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों के इलाकों में आंशिक या अस्थायी कटौती की गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेघरता की दर प्रति 10000 लोगों पर 13 है। अर्थात 17 प्रतिशत लोगों के पास अपना घर नहीं है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35 प्रतिशत गांवों में स्थानीय स्तर पर कोई भी बुनियादी चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और सर्जनों की भारी कमी है, जो लगभग 80 प्रतिशत तक खाली पड़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों (2014–15 से 2024–25) में देश भर में करीब 94000 सरकारी स्कूल बंद या आपस में मर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 25 स्कूलों पर ताला लगा है।

इसी दशक में सरकारी स्कूलों में कुल छात्रों का नामांकन 2.26 करोड़ कम हुआ है, जो 2014–15 के 26.95 करोड़ से घटकर 2024–25 में 24.69 करोड़ रह गया है। देश के एक लाख से अधिक स्कूलों में आज भी बिजली की उचित सुविधा नहीं है, और कई स्थानों पर पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। 71959 स्कूलों में लड़कियों के लिए और 1.12 लाख स्कूलों में लड़कों के लिए काम करने वाले शौचालय मौजूद नहीं हैं।

1.39 लाख स्कूलों में लाइब्रेरी और 2.65 लाख स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी का अभाव तो लगभग 13.62 लाख स्कूलों में है। भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर जून 2026 में बढ़कर 16.2 फीसदी हो गई है। 15–29 आयु वर्ग की महिलाओं में यह दर बढ़कर 20.7 फीसदी हो गई। इसी आयु वर्ग के पुरुषों में यह दर 14.6 फीसदी दर्ज की गई। जून 2026 में शहरी युवा बेरोजगारी दर 18.2 फीसदी और ग्रामीण युवा बेरोजगारी दर 15.1 फीसदी रही। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक गरीबी वाले राज्य बिहार में 51.91 फीसदी आबादी गरीब है। झारखंड में 42.16 फीसदी लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में 37.79 फीसदी जनसंख्या गरीब है। मध्य प्रदेश में 36.65 फीसदी लोग गरीब हैं। भारत में सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 65 फीसदी हिस्सा है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 फीसदी लोग राष्ट्रीय आय का 58 फीसदी हिस्सा पाते हैं, जबकि सबसे निचले 50 फीसदी लोगों को सिर्फ 15 फीसदी मिलता है। आर्थिक असमानता की यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का यह हक है कि जीडीपी की ग्रोथ पर खुशी मनाने का आह्वान करें, पर जब तक इसका असर देश की मूल समस्याओं के निराकरण में नजर नहीं आएगा, देश के लोगों की उदासी दूर नहीं होगी। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार देना होगा। बड़ी संख्या में युवा अभी बेरोजगार हैं। उन्हें उनकी शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, फिर भी अभी और काम करने की जरूरत है। रोजगार मिलने से कई समस्याएं हल हो जाएंगी।

—**योगेंद्र योगी**

सिर्फ हस्ताक्षर नहीं अधिकार है साक्षरता

हर वर्ष 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षर का मतलब होता है – पढ़ने-लिखने में सक्षम व्यक्ति। मतलब यह है कि जो व्यक्ति पढ़ और लिख सकता हो तथा लिखी हुई बात को समझ सकता हो,साक्षर कहलाता है।इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य शिक्षा और साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को ज्ञान और सूचना से जोड़ने का माध्यम साक्षरता ही है। जब कोई व्यक्ति साक्षर होता है तो वह शिक्षा के माध्यम से ज्ञान और सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और जब व्यक्ति के पास ज्ञान और सूचनाएं होती हैं, तो वह व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकता है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण और अहम् योगदान दे सकता है। सच तो यह है कि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंच बहुत ही जरूरी हो गई है, क्यों कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही आज के एआइ तथा डिजिटल युग में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और सूचना की सही पहचान कर सकता है। वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों। शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि शिक्षा व्यक्ति को केवल और केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं देती है, बल्कि यह व्यक्ति विशेष को जीवन में आत्मनिर्भर, अधिक जागरूक और अधिकार-संपन्न भी बनाती है। यदि हमें किसी राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो शिक्षा ही वह अनमोल रत्न है, जो उस राष्ट्र विशेष को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकता है।

सोन जल समझौते से सहकारी संघवाद की नई राह

अंतरराज्यीय नदियाँ केवल बहते पानी की नदियाँ ही नहीं हैं, बल्कि ये जीवन रेखाएँ हैं जो कृषि उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, उद्योगों, पारिस्थितिकी तंत्र और लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देती हैं। हालाँकि, नदियों का प्रवाह राज्य की सीमाओं को भी पार कर सकता है, इसलिए इनका प्रबंधन राज्यों के बीच टकराव का कारण बन सकता है। हाल ही में बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी को लेकर हुआ समझौता, जिसका उद्देश्य लगभग 25 वर्षों से चले आ रहे जल विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करना है, सतत जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
झु एक ऐसा जल मुद्दा जिसे केवल सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है, न कि टकराव से। अंतरराज्यीय जल संघर्षों के निरंतर बने रहने का मुख्य कारण जल विकास के लिए परस्पर विरोधी हित हैं। एक राज्य सिंचाई के लिए अधिक जल का उपयोग कर सकता है, जबकि दूसरा पेयजल, उद्योग या शहरी विकास के लिए। ये सभी आवश्यकताएँ जायज़ हैं, लेकिन जल सीमित है। यदि कई राज्य एक ही नदी पर निर्भर हैं, तो संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं और इन आवश्यकताओं को संतुलित करना संघीय प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है। विभिन्न क्षेत्रों और ऋतुओं में जल असंतुलन से जटिलताएं और बढ़ जाती हैं। मानसून के मौसम में अच्छी वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में उस दौरान भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी हो सकती है। इस प्रकार, एक नदी एक वर्ष भरपूर जल से भरी हो सकती है और दूसरे वर्ष विरल हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति और भी अनिश्चित होती जा रही है। वर्षा के बदलते पैटर्न से नदियों के प्रवाह में परिवर्तन हो रहा है, जबकि लंबे समय तक सूखा पड़ने और चरम मौसम की घटनाएँ भी जल उपलब्धता को प्रभावित कर रही हैं और जल उपलब्धता के बारे में अनुमानों को कम विश्वसनीय बना रही हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन से ऐतिहासिक समझौतों पर असहमति भी उत्पन्न हो सकती है। बिहार-झारखंड संबंधों के मामले में भी यही स्थिति है। एक ही प्रशासनिक ढांचे के भीतर हुए समझौतों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है यदि राज्यों का पुनर्गठन हो और उनकी कृषि, जनसंख्या और आर्थिक आवश्यकताएं विकसित हों। दशकों पहले प्रचलित निष्पक्षता की अवधारणा वर्तमान संदर्भ में लागू होना आवश्यक नहीं है। संघर्ष का एक अन्य बड़ा कारण ऊपरी इलाकों में चल रही परियोजनाओं का विकास और उनका उपयोग है। बांधों, बैराजों और सिंचाई योजनाओं के कारण निचले इलाकों में पानी की मात्रा और निकासी का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। सूचना



साझाकरण और राज्यों के बीच परियोजना समन्वय के अभाव में, ताकि यह एक लंबा संघीय संघर्ष न बन जाए। सोन नदी के लिए बिहार-झारखंड का दर्जा समझौता वार्ता के महत्व का एक उदाहरण है। दोनों विवादों को और बढ़ा देती है। राज्यों के बीच आवंटित जल की मात्रा और उपलब्ध जल की मात्रा को लेकर अलग-अलग लक्ष्य हो सकते हैं। यदि वर्षा की मात्रा, नदी के प्रवाह, जलाशयों के स्तर और जल उपयोग के बारे में कोई साझा, वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो बातचीत आसानी से परस्पर विरोधी मांगों पर बहस में बदल सकती है। अगर लोग राजनीतिक रूप से संगठित हो जाते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अर्थात का मुद्दा भावनात्मक है और इसका किसानों, परिवारों और स्थानीय पर्यटकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर तकनीकी समस्या क्षेत्रीय मुद्दा या राजनीतिक विवाद बन जाती है, तो

समझौता करना मुश्किल हो जाता है। संस्थागत संवाद का यही उद्देश्य है, ताकि यह एक लंबा संघीय संघर्ष न बन जाए। सोन नदी के लिए बिहार-झारखंड का दर्जा समझौता वार्ता के महत्व का एक उदाहरण है। दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से समाधान खोजने के लिए एक-दूसरे से संपर्क साधकर अहिंसक तरीके से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार को 575 करोड़ एकड़-फीट (क्लर) और झारखंड को 2 करोड़ एकड़-फीट (क्लर) जल आवंटन प्राप्त हुआ है। लेकिन इस समझौते का प्रभाव केवल इन आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी हैं। इसका वास्तविक महत्व यह संदेश देना है कि राज्य अपने हितों की रक्षा करने के साथ-साथ अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को भी समझने में सक्षम हैं। बातचीत से साझा अवसरचना के बेहतर उपयोग के अवसर भी मिल सकते हैं। खंडित जल

महिला एशिया कप: भारत जीता तो फिर ट्रॉफी पर फंस सकता है पैच! फाइनल देखने पहुंच सकते हैं नकवी, ड्रामे की आशंका

दुबई। एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर पिछले साल हुआ विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अब महिला एशिया कप में भी ऐसा ही मामला सामने आने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी 13 सितंबर को होने वाले महिला एशिया कप फाइनल के लिए दुबई में मौजूद रहेंगे। उन्हें समापन समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है। नकवी के फाइनल में मौजूद रहने और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने की संभावना के कारण 2025 के पुरुष एशिया कप फाइनल जैसा विवाद दोबारा खड़ा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

फाइनल में चीफ गेस्ट होंगे मोहसिन नकवी

जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहसिन नकवी 13 सितंबर को महिला एशिया कप के फाइनल में शामिल होंगे। उन्हें टूर्नामेंट के समापन समारोह के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया है। ऐसे में अगर भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंचकर खिताब जीतती है तो ट्रॉफी सौंपने को लेकर स्थिति पेचीदा हो सकती है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली



भारतीय टीम टूर्नामेंट में खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है और वह पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। ऐसे में अगर भारत फाइनल जीतता है तो टीम और नकवी के बीच ट्रॉफी लेने को लेकर फिर गतिरोध पैदा होने की संभावना जताई जा रही है।

भारत-पाकिस्तान मैच में भी नहीं मिला था हाथ

भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया मुकाबले के दौरान भी दोनों टीमों के कप्तानों के बीच हेंडशेक नहीं हुआ था। हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने मैच के दौरान हाथ नहीं मिलाया था। पिछले साल पुरुष एशिया कप में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था। उस

समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के बीच हेंडशेक नहीं हुआ था। इसके बाद दोनों टीमों के बीच तनाव और प्रोटोकॉल को लेकर काफी चर्चा हुई थी।

2025 पुरुष एशिया कप फाइनल में क्या हुआ था?

2025 के पुरुष एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद पुरस्कार समारोह में मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए कथित तौर पर करीब आधे घंटे तक पोटियम पर इंतजार करते रहे। हालांकि, सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया

था। भारतीय टीम चाहती थी कि ट्रॉफी किसी अन्य एसीसी अधिकारी के हाथों सौंपी जाए। टीम इंडिया ने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी कि नकवी से वे ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसके बावजूद जानबूझकर नकवी स्टेज पर खड़े रहे थे।

नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे

इसके बाद मोहसिन नकवी ने पुरस्कार समारोह छोड़ने का फैसला किया और ट्रॉफी चुराकर अपने साथ ले गए। वह ट्रॉफी को अपने होटल के कमरे में ले गए थे। इसके बाद से ट्रॉफी एसीसी के दुबई स्थित कार्यालय में रखे होने की बात सामने आती रही है और भारतीय टीम को अभी तक वह ट्रॉफी नहीं मिली है।

भारत आने वाली ब्राजील की फुटबॉल टीम का ऐलान नौ को

ब्राजीलिया। ब्राजील की मेंस फुटबॉल टीम के कोच कालों एसेलोटी नौ सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाले फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच के लिए 26 सदस्यीय टीम का ऐलान करेंगे। ब्राजीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने इसकी जानकारी दी। भारत और ब्राजील के बीच मैच तीन अक्टूबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 31 अगस्त को अपनी टीम घोषित कर चुका है, लेकिन ब्राजील के भारत आने वाले खिलाड़ियों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं।

भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी चाइना मास्टर्स चैंपियन

शेनझेन। भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने रविवार को चीन के हे जी टिंग और रेन शियांग यू को एक घंटे 10 मिनट चले मैच में 11-21, 21-13, 21-17 से हराया। यह टाइलेंट वर्ल्ड नंबर-5 भारतीय जोड़ी के लिए बड़ी जीत है। दोनों 19 सितंबर से जापान में होने वाले एशियन गेम्स में अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने उतरेंगे। चिराग-सात्विक को 92 हजार यूएस डॉलर की इनामी राशि मिली।

बिना कोच के पदक पर दावा ठोकेगी एशियाई चैंपियन: एशियाई खेलों में कराटे टीम को चाहिए था कोच, भेजा जा रहा मैनेजर

एजेंसी ॥ नई दिल्ली

एशियाई खेलों में पदक की बड़ी दावेदार और जून में एशियाई चैंपियन बनीं कराटे खिलाड़ी अलीशा चौधरी बिना कोच के दावेदारी पेश करने जा रही हैं। एशियाई खेलों में अलीशा (55 किलो) और चेतन भट्ट (84 किलो) कराटे में भारतीय चुनौती पेश करेंगे, लेकिन इन दोनों के साथ कोच नहीं बल्कि टीम लीडर (मैनेजर) भेजा जा रहा है। टीम लीडर को मैट पर बतौर कोच बैठने की मंजूरी नहीं होगी। कोचिंग कॉर्नर में बैठा कोच अपने खिलाड़ी के साथ अन्याय होने की स्थिति में रिव्यू लेता है। अलीशा का कहना है कि वह अपने कोच विकास को साथ भेजने की गुहार आईओए से लगा रही हैं, लेकिन अंत में एक ऐसे टीम लीडर आदिकेशवा पेरुमल को उनके साथ भेजा जा रहा है, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं है।

अलीशा का जाना तय नहीं था

कराटे की फेडरेशन में विवाद होने के कारण जुलाई माह तक यह तय हो गया था कि कराटे की टीम एशियाड में नहीं खेलेगी, लेकिन मामला खेल मंत्री मनसुख मांडविया के पास पहुंचा तो उन्होंने इस



दौरान उन्हें तैयारियों के लिए कोच के साथ 20 अगस्त से तीन सितंबर तक इस्तांबुल (तुर्किये) भी भेजा गया। अलीशा का कहना है कि उन्हें टीम लीडर से ज्यादा कोच की जरूरत है। कोच वजन के दौरान भी उनके साथ होता। कोच वजन सेट कराता है। उसके पास कोचिंग का लाइसेंस होता है। आईओए के अधिकारी का कहना है कि लांग लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण कोच नहीं जा रहा है, लेकिन उनके पास यह जवाब नहीं था कि टीम लीडर को फिर कैसे भेजा जा रहा है।

वर्ष बाली में एशियाई चैंपियन बनने वाली अलीशा और 5वें स्थान पर रहने वाले चेतन भट्ट को एशियाई खेलों में भाग लेने की मंजूरी दिलवाई। कराटे के किसी भी कोच का नाम एशियाई खेलों की लांग लिस्ट में नहीं डाला गया था। जब अलीशा का एशियाड में जाना तय हो गया तो उन्होंने बीते माह आईओए से अपने कोच को साथ भेजने की गुहार लगाई।

वजन सेट कराता है कोच

अलीशा ने आईओए से कई बार संपर्क साधा। इस

सच बाजार

नवी मुंबई के आरसीपी से चलती जियो की डिजिटल रफ्तार 550 एकड़ के रिलायंस कॉरपोरेट पार्क में जियो का कॉरपोरेट संचालन, नेटवर्क मॉनिटरिंग और तकनीकी ढांचा

वाणिज्य संचाददाता.भोपाल/ मुंबई

नवी मुंबई के घनसोली स्थित रिलायंस कॉरपोरेट पार्क (आरसीपी) रिलायंस समूह की प्रमुख कॉरपोरेट रिसर्पत्तियों में शामिल है। करीब 550 एकड़ में फैले इस परिसर में विभिन्न कॉरपोरेट और तकनीकी गतिविधियां संचालित होती हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा कॉरपोरेट ढांचा भी इसी परिसर का हिस्सा है। बड़े भू-भाग में विकसित आरसीपी में कार्यालयों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सुविधाएं, नेटवर्क संचालन से जुड़ी व्यवस्थाएं और हरित क्षेत्र मौजूद हैं।

आरसीपी में प्रवेश और परिसर के भीतर आवाजाही निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत होती है। कर्मचारियों, वाहनों और आगंतुकों के लिए अलग-अलग स्तर की पहुंच व्यवस्था लागू है। परिसर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश अनुमति के आधार पर नियंत्रित



किया जाता है। बड़े क्षेत्रफल में फैले होने के कारण आरसीपी का संचालन एक संगठित कॉरपोरेट कैपेस की तरह किया गया है। हालांकि इसकी सुरक्षा व्यवस्था की तुलना अनौपचारिक तौर पर सैन्य परिसर से की जा सकती है, लेकिन आरसीपी सैन्य प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि रिलायंस समूह का कॉरपोरेट परिसर है।

जियो के शुरुआती दौर से जुड़ा रहा आरसीपी

रिलायंस जियो के शुरुआती

विस्तार के दौरान आरसीपी का इस्तेमाल कंपनी के कॉरपोरेट और प्रबंधन संबंधी कार्यों के लिए किया गया। 2015 के आसपास की रिपोर्टों में जियो के शीर्ष नेतृत्व के आरसीपी स्थित पीसीटीसी-22 के ओपन-ऑफिस में काम करने का उल्लेख मिलता है। उस दौर में जियो के कार्यस्थल में ओपन-ऑफिस व्यवस्था पर जोर दिया गया था। इसमें पारंपरिक अलग-अलग केबिनों की तुलना में टीम आधारित कार्य और सहयोग को प्राथमिकता देने की

कोशिश की गई। जियो का कारोबार मोबाइल कनेक्टिविटी के अलावा ब्रॉडबैंड, डिजिटल सेवाओं, मनोरंजन, स्मार्ट डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। एक्सपीरियंस सेंटर में इन तकनीकों और सेवाओं की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। आरसीपी में नेटवर्क संचालन से जुड़ी तकनीकी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर जैसे केंद्रों में नेटवर्क की स्थिति, ट्रैफिक और तकनीकी प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों की निगरानी की जाती है। देशभर में बड़े पैमाने पर मोबाइल और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जियो को रेडियो नेटवर्क, फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, साफ्टवेयर सिस्टम और नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसी कई तकनीकी व्यवस्थाओं को एक साथ संचालित करना पड़ता है। नेटवर्क ऑपरेशंस से जुड़ी व्यवस्था इसी तकनीकी ढांचे की

निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 550 एकड़ में फैले आरसीपी में कार्यालयों के साथ तकनीकी सुविधाएं और हरित क्षेत्र भी विकसित किए गए हैं। परिसर की संरचना में बड़े कार्यालय भवनों के अलावा खुले स्थान और पेड़-पौधों वाले क्षेत्र शामिल हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नेतृत्व में शुरू हुआ जियो का डिजिटल कारोबार अब समूह के प्रमुख व्यवसायों में शामिल है। आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन हैं, जबकि ईशा अंबानी रिलायंस के रितेल कारोबार की प्रमुख जिम्मेदारियों में हैं।

नई पीढ़ी के नेतृत्व के साथ रिलायंस समूह के डिजिटल और रितेल कारोबार का विस्तार जारी है। आरसीपी इसी व्यापक कारोबारी ढांचे का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां कॉरपोरेट प्रबंधन, तकनीकी संचालन और डिजिटल कारोबार से जुड़ी गतिविधियां एक ही परिसर में संचालित होती हैं।

एचवाईबीई इंडिया ऑडिशन की 8 नए शहरों में होगी टैलेंट की तलाश

भोपाल। एचवाईबीई इंडिया नेऑडिशन की अगली कड़ी एचवाईबीई इंडिया ऑडिशन- फाइनल कॉल’ का ऐलान किया है। पहले राउंड को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद अब कंपनी देश के 8 और शहरों में पहुंचकर नए कलाकारों की तलाश करेगी। एचवाईबीई इंडिया के अनुसार, ऑडिशन को देशभर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिभागियों ने आवेदन किया। इसके अलावा दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले भारतीयों ने भी ऑडिशन में हिस्सा लिया। अब तक 116 देशों के करीब 1,650 शहरों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सेमसंग ने किया यूएसबी 4 से लैस पी9 और पी7 कॉम्बैट एसएसडी प्रदर्शित

कोलोन। सेमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने गेम्सकॉम 2026 में यूएसबी 4 कनेक्टिविटी से लैस अपनी अगली पीढ़ी की पी9 और पी7 पोर्टेबल एसएसडी सीरीज पेश की। कंपनी के अनुसार, नई सीरीज को अल्ट्रा-हाई-रिज़ॉल्यूशन वीडियो, एआई कंटेंट और बड़े आकार के गेम्स की बढ़ती स्टोरेज जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।नई रेंज में पी9 प्लैगशिप मॉडल है, जिसे प्रोफेशनल और हाई-परफॉर्मेंस वर्कफ्लो के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं पी7 को रोजमर्रा के उपयोग में तेज और सुविधाजनक एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पर पेश किया गया है।

यूनियन बैंक ने आइडिया 2.0 हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले का किया आयोजन

मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 3 सितंबर 2026 को के. जे. सोमैया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के ऑडिटोरियम, विद्याविहार (पूर्व), मुंबई में पीएसबी हैकथॉन सीरीज 2026 के अंतर्गत आइडिया 2.0 हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया। सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस हैकथॉन का उद्देश्य विचारकों, नवप्रवर्तकों, छात्रों और पेशेवरों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना था, जहां वे बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों



योजना को भी अहम बताया गया।

सरकार ने उद्योग के साथ साझेदारी पर दिया जोर

केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण संवर्धन योजना महत्वपूर्ण उपकरणों और कलपुर्जों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इससे घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शी नीलामी व्यवस्था से निवेश, प्रतिस्पर्धा और तकनीक को बढ़ावा मिला है।

के लिए नए और तकनीक आधारित समाधान विकसित कर सकें। ग्रैंड फिनाले के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आशीष पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक नितेश रंजन और अमरेश प्रसाद ने प्रतिभागियों एवं उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सरकार द्वारा नामित निदेशक डॉ. देबाशीष फ़स्टी ने भी वचुंअल माध्यम से सभा को संबोधित किया।

मिवी का पहला स्मार्टफोन ‘मिवी वन’ 24 को लांच

भोपाल। घरेलू कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में शामिल मिवी ने स्मार्टफोन कैटेगरी में प्रवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ड्रालकॉम, फ्लिपकार्ट और गूगल के साथ साझेदारी में अपना पहला स्मार्टफोन ‘मिवी वन’ 24 सितंबर 2026 को लॉन्च करेगी। यह स्मार्टफोन विशेष रूप से केवल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के अनुसार, अपने सेगमेंट में मिवी वन भारत का एकमात्र स्मार्टफोन होगा, जिसमें स्लैपड्रैगन 5जी चिपसेट दिया जाएगा।

इनफिनिक्स हॉट 70 प्रो भारत में लांच

नई दिल्ली। स्मार्टफोन ब्रांड इनफिनिक्स ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन हॉट 70 प्रो लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक, यह फोन युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें आकर्षक डिजाइन, इंटरैक्टिव अनुभव और बेहतर रोजमर्रा की परफॉर्मेंस का संयोजन देखने को मिलता है। फोन में कंपनी का नया डायनामिक शाइन डिज़ाइन दिया गया है, जो रंग और टेक्सचर को स्मार्टफोन के अनुभव का हिस्सा बनाता है। इनफिनिक्स इंडिया के सीएमओ मिराज गुप्ता ने कहा कि आज के स्मार्टफोन केवल ज्यादा स्मार्ट होने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें यूजर की पर्सनैलिटी को भी व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए।

